RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 15 JULY TO 21 JULY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 47 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

चीन से घटा भारत का आपसी व्यापार, अमेरिका के साथ बढ़ा Page 2

बढ़ते संक्रमण के कारण फिर से लॉकडाउन की ओर भारत Page 3

डिफेंस के लिए महिंद्रा ने उतारा बख्तरबंद वाहन Page 7

editoria!

संकट में प्रवासी भारतीय

कोविड 19 से उपजे हालात के साइड इफेक्ट के तौर पर एक और समस्या देश के सामने आ खड़ी हुई है। कई खाड़ी देशों से बेरोजगार होकर प्रवासी कामगारों की बड़ी तादाद भारत लौट चुकी है लेकिन अब उनकी वापसी की संभावना पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कुवैत की नैशनल असेंबली में एक बिल लाया जा रहा है जिसका मकसद देश में प्रवासियों की संख्या में जबर्दस्त कमी लाना है। अभी कुवैत की कुल आबादी का 70 फीसदी हिस्सा प्रवासियों का है जिसे कम करके 30 फीसदी तक लाने का इरादा इस बिल में जताया गया है। वहां प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। माना जा रहा है कि यह बिल इसी रूप में अमल में आ गया तो करीब 8 लाख प्रवासी भारतीयों का कुवैत से साथ छूट जाएगा। ध्यान रहे, 2018 में सिर्फ कुवैत से ही करीब 4.8 अरब डॉलर भारत भेजे गए थे। यूं भी प्रवासियों की नियमित कमाई प्राप्त करने में भारत दुनिया में अव्वल है। 2018 में यह राशि देश के जीडीपी का 2.9 फीसदी आंकी गई थी। अभी कोरोना और तेल कीमतों में गिरावट के मिले-जुले प्रभाव का नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि प्रवासी भारतीयों पर चौतरफा संकट आ पड़ा है। बिल भले कुवैत में आ रहा हो पर समस्या कुवैत तक सीमित नहीं है। सारे खाड़ी देश कोरोना और सस्ते तेल की दोहरी मार झेल रहे हैं और समाधान प्रवासियों की संख्या घटाने में देख रहे हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं। जब भी इन देशों पर कोई आफत आती है, सबसे पहले उनकी नजर बाहर से आकर काम कर रहे लोगों पर ही जाती है। यह अलग बात है कि इससे उनकी बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं निकलता। सऊदी अरब सबसे पहले ऐसे उपाय घोषित करने वाला देश रहा है। 1975 में वहां के कुल कामगारों में 75 फीसदी मूल निवासी और 25 फीसदी प्रवासी थे। पर 40 साल बाद 2015 में प्रवासी कामगारों का प्रतिशत घटने के बजाय बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया। ऐसा सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, तमाम खाड़ी देशों में हुआ है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात में 95 फीसदी, कुवैत में 86 फीसदी, ओमान में 81 फीसदी और बहरीन में 73 फीसदी कामगार दूसरे मुल्कों के हैं। इसके पीछे कम मजदूरी ही नहीं काम की क्वॉलिटी की भी बड़ी भूमिका है। जो काम प्रवासी करते हैं, उन्हें करने में इन देशों के मूल निवासी अपनी हेठी समझते हैं। संभवतः इन्हीं वजहों से कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासी विरोधी राजनीतिक-प्रशासनिक कदमों का कोई खास प्रभाव लंबे समय के लिए नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के लिए भी अगर प्रवासी भारतीयों को बेरोजगार रहना पड़ा तो भारत को न सिर्फ उनके लिए कुछ इंतजाम करने होंगे, बल्कि विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर बड़ा झटका भी झेलना पड़ेगा।

200 करोड़ तक की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं करके घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की प्रगति की समीक्षा करने के बाद मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में दी गई। बयान के अनुसार, देश के एमएसएमई (सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम) को बड़ी राहत देते हुए व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के वर्तमान नियम 161 (पअ) और वैश्विक निविदाओं से संबंधित जीएफआर नियमों में संशोधन किए हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब 200 करोड़ रुपये तक की निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा पूछताछ या ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीआई) तब तक आमंत्रित नहीं की जाएगी जब तक कि कैबिनेट सचिवालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न हो जाए। बयान में कहा गया कि वित्तमंत्री ने यह घोषणा की है कि रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां अनुबंधात्मक या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 माह तक का समय विस्तार देंगी, जिनमें ईपीसी और रियायत समझौतों से संबंधित दायित्व भी शामिल हैं।

एमएसएमई को मिलेगा प्रोत्साहन

घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन

इस संबंध में व्यय विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि (कोविड-19 महामारी के कारण) अप्रत्याशित परिस्थिति या आपदा से जुड़ी धारा (एफएमसी) का उपयोग करके ठेकेदार या रियायत प्राप्तकर्ता पर कोई भी खर्च या जुमार्ना थोपे बिना ही अनुबंध की अवधि को कम-से-कम तीन माह और अधिक-से-अधिक छह माह बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदार या आपूर्तिकर्ताओं को कार्य-प्रदर्शन संबंधी सिक्योरिटी के मूल्य को वापस करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए जो बाकायदा की जा चुकी आपूर्ति या कुल अनुबंध मूल्य के पूरे हो चुके अनुबंध कार्य के अनुपात में होगा। इसे विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा लागू किया जा रहा है।

अतिरिक्त 2 फीसदी कर्ज ले सकते हैं राज्य

मंत्रालय ने साथ ही कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राजस्व में कमी को लेकर चालू वित्त वर्ष में राज्यों को उनके अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के दो प्रतिशत के बराबर और उधार लेने के बारे में राज्यों को लिखा है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित वृहद पैकज के तहत राज्यों की कर सीमा जीएसडीपी के तीन से बढ़ा कर पांच प्रतिशत कर दी गयी है। सीतारमण ने मई में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने पैकेज की घोषणा करते हुए बताया था कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिये राज्यों के उधार लेने की सीमा को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इससे राज्यों को अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

हालांकि उन्होंने तब कहा था कि यह अतिरिक्त उधार राज्यों को कुछ तय सुधार करने पर ही प्राप्त होंगे। इन सुधारों में एक देश, एक राशन कार्ड को अपनाना, कारोबार सुगमता, बिजली वितरण और स्थानीय शहरी निकायों के राजस्व से जुड़े हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का समर्थन करने के प्रयास में व्यय विभाग ने अनुमानित जीएसडीपी के दो प्रतिशत के अतिरिक्त उधार के लिये सभी राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया है।'

पीएमईएसी के सदस्य ने कहा

भारत को निर्यात 'महाशक्ति' बनाने के लिए अवांछित नियमों से निजात जरूरी

मुंबई। एजेंसी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के अस्थायी सदस्य वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि भारत को निर्यात क्षेत्र में 'महाशक्ति' बनाने के लिए अवांछित नियमों से निजात पाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवांछित नियमों को समाप्त करने से निर्यात क्षेत्र में चीन का अनुकरण करने के लिए भारत को एक शुरुआत मिलेगी। अकादमिक संस्थान एसपीजेआईएमआर द्वारा मंगलवार को आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने निर्यात क्षेत्र में भारत को एक बड़ी ताकत बनाने के लिए शुरुआत करने की वकालत की। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर है जिसकी वजह से निर्यात करना मुश्किल है। क्रिया विश्वविद्यालय से जुड़े नागेश्वरन ने कहा, "हम अभी जिस स्थिति में हैं, मसलन हमारे कारोबार की ऊंची लागत और विधायी और अनुपालन के बोझ, वहां से हम चीन का अनुकरण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वियतनाम, मेक्सिको और बांग्लादेश अपने उद्योग चीन से हटा रहे हैं, भारत से नहीं। अभी हम वहां हैं ही नहीं। घरेलू बाजार के बारे में नागेश्वरन ने कहा कि 80 प्रतिशत आबादी के लिए उत्पाद बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद पर कितनी लागत बैठ रही है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर लागू अनुपालन का बोझ चिंता बढ़ाता है। उन्होंने कहा, "ऐसे में स्पष्ट रूप से इन अवांछित नियमों, अंकुशों और नियमनों से निजात पाने की नीति एक शुरुआत होगी। ऐसा करने पर सरकार कारोबार से निकल सकेगी और एक स्पष्ट मध्यम अवधि का वृद्धि लक्ष्य दे सकेगी।" नागेश्वरन ने निर्यात बढ़ाने के प्रयासों को एक 'प्रक्रिया' बताते हुए कहा कि इस तरह का दबदबा तीन या छह महीने में हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने इस दिशा में एक शुरुआत करने की वकालत की।

रुपया 27 पैसे उछलकर 75.15 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के रुख और अमेरिकी डालर में कमजोरी से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को रुपया, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 27 पैसे उछलकर 75.15 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि भारत में कोविड-19 के टीके का इंसान पर चिकित्सकीय परीक्षण शुरु होने के बाद निवेशकों की धारणा में मजबूती आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया सुबह 75.35 पर खुला और बाद में इसमें तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 27 पैसे की तेजी दर्शाती 75.15 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 75.42 पर बंद हुआ था। चार घंटे के कारोबारी सत्र में घरेलू मुद्रा ने डॉलर के मुकाबले 75.14 के उच्चतम और 75.36 के निम्नतम स्तर को छुआ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के संभावित टीके का इंसानों पर चिकित्सकीय परीक्षण देश में शुरु किया गया है। इससे निवेशकों में उत्साह दिखा।

सउदी अरामको के साथ सौदा तय समय के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाया है: अंबानी

मुंबई। एजेंसी

एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने बुधवार को कहा कि कोविड- 19 की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह में सउदी अरामको के साथ 15 अरब डालर की हिस्सेदारी बिक्री की योजना तय समय के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकी है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक के मौके पर कहा, ''हम अरामको के साथ अपने दो दशक लंबे रिश्तों का मूल्य समझते हैं, हम उनके साथ दीर्घकालिक भागीदारी के लिये प्रतिबद्ध हैं।'' उन्होंने हालांकि, इस बारे में कुछ नहीं कहा कि सौदे को लेकर सही दिशा में आगे बढ़ने अथवा इसके पूरा होने को लेकर कोई नई समयसीमा भी नहीं बताई। मुकेश ने कहा, ''ऊर्जा क्षेत्र में अप्रत्याशित स्थिति और कोविड- 19 महामारी के कारण सउदी अरामको के साथ सौदा तय समयसीमा के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया।'' उन्होंने कहा कि कंपनी में कई पक्षों को भागीदारी का अवसर देने के लिये रिलायंस अपने तेल- पेट्रो रसायन कारोबार को अलग अनुषंगी के तौर पर खड़ा करना चाहता है। इस प्रक्रिया को हम 2021 की शुरुआत तक पूरा कर लेने की उम्मीद कर रहे हैं।'' मुकेश अंबानी ने पिछले साल अगस्त में तेल- पेट्रो रसायन कारोबार में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी सउदी अरामको को करने की घोषणा की थी। यह सौदा मार्च 2020 तक पूरा होना था लेकिन इसमें देरी हुई है। तेल से लेकर पेट्रो रसायन कारोबार में रिलायंस की गुजरात के जामनगर स्थित दो रिफाइनरियां और पेट्रो-रसायन परिसंपत्तियां शामिल होंगी। कंपनी की नई सालाना रिपोर्ट में अंबानी ने कोई समयसीमा दिये बिना कहा है कि रिलायंस सउदी अरामको के साथ रणनीतिक भागीदारी को पूरा करने के लिये काम कर रही है। अरामको के साथ भागीदारी से कंपनी की जामनगर रिफाइनरी की विभिन्न ग्रेड के कच्चे तेल की सुविधा और कच्चे माल की बेहतर सुरक्षा उपलब्ध होगी। अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने ईंधन के खुदरा कारोबार उद्यम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बीपी को 7,629 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा पूरा कर लिया है।

कोविड- 19 महामारी के दौरान तस्करी में तेजी के खतरे पर निगरानी रखे सरकार: फिक्की कास्केड

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग मंडल फिक्की की एक समिति ने बुधवार को कहा कि देश के समक्ष खासतौर से मौजूदा कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक संकट के इस दौर में अवैध व्यापार सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और सरकार को इस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। तस्करी और नकली कारोबारी गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को नुकसान पर गठित फिक्की की समिति (कोस्केड) ने कहा कि कोविड- 19 महामारी के इस दौर में सोना, सिगरेट, शराब जैसे सामान की तस्करी के कई मामले सामने आये हैं। फिक्की कास्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत ने यहां जारी वक्तव्य में कहा, ''अवैध कारोबार करने वाले लोग अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये नये नये तरीकों की खोज में रहते हैं। इस तरह की गतिविधियों से राष्ट्र को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है और समाज को इसकी भारी लागत चुकानी पड़ती है।'' फिक्की की इस इकाई ने नीति निर्माताओं से कहा है कि वह अवैध व्यापार को ''राष्ट्रीय खतरा'' मानें। उसने कहा है कि अवैध कारोबार देश के समक्ष आज सबसे भयंकर चुनौती बन गई है। खासतौर से वर्तमान में कोविड- 19 के इस दौर में जब आर्थिक संकट छाया हुआ है यह चुनौती और भी खतरनाक हो गई है।'' फिक्की कास्केड में हाल ही में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई और हैदराबाद में सिगरेट की तस्करी पकड़े जाने, केरल में सोने की बड़ी खेप पकड़े जाने का उदाहरण देते हुये कहा कि तसकरी से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान होता है बल्कि इससे स्थानीय उद्योगों को भी कारोबार का भारी नुकसान होता है जिनसे कई लोगों की जीविका जुड़ी होती है। राजपुत ने तस्करी का माल पकड़ने में प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों की प्रशंस् करते हुये हा कि सरकार ने इस स्थिति पर अंकुश लगाना होगा। ऐसे समय जब देश पहले ही कोरोना वायरस के कारण आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त संकट से निपटने में लगी है यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार अवैध व्यापार गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, 513.25 अरब डॉलर हुआ आंकड़ा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 जुलाई को खत्म हफ्ते के दौरान 6.47 अरब डॉलर की बड़ी वृद्धि के साथ 513.25 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. इससे पहले 26 जून को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 अरब डॉलर बढ़कर 506.84 अरब डॉलर पर पहुंचा था। 5 जून को खत्म हफ्ते में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर गया था। उस समय यह 8.22 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर पहुंचा था।

विदेशी मुद्रा भंडार में 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में आई तेजी का कारण कुल मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी मुद्रा आस्तियों का बढ़ना है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन हफ्ते में विदेशी मुद्रा आस्तियां 5.66 अरब डॉलर बढ़कर 473.26 अरब डॉलर हो गईं।

स्वर्ण भंडार में भी बढ़ोतरी

रिजर्व बैंक के अनुसार, समीक्षाधीन हफ्ते में स्वर्ण आरक्षित भंडार 49.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 34.02 अरब डॉलर हो गया. रिजर्व बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि समीक्षाधीन हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर बढ़कर 1.45 अरब डॉलर जबकि आईएमएफ में देश का आरक्षित मुद्रा भंडार 25.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.52 अरब डॉलर हो गया।

नेफ्रोप्लस ने शुरू की 'डायलिसिस ऑन व्हील' सेवा

नयी दिल्ली। एजेंसी

नेफ्रोप्लस ने मंगलवार को 'डायलिसिस ऑन व्हील' सेवा की शुरूआत की। इसके तहत मरीजों को उनके घरों के पास जाकर एंबुलेंस के भीतर डायलिसिस कराने की सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 संकट को देखते हुए मरीज और चिकित्सक दोनों ही घर पर डायलिसिस कराने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में यह 'डायलिसिस ऑन व्हील' की सेवा शुरू करने का मकसद इसकी लागत को कम करना है। इससे मरीजों को भी इसे अपनाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने कहा कि शुरुआत में इस सेवा को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से देश के 20 शहरों तक बढ़ाने की योजना है। नेफ्रोप्लस डायलिसिस सेवाएं देने वाली एक प्रमुख कंपनी है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम वुप्पला ने कहा कि डायलिसिस ऑन व्हील की अनोखी सेवा शुरू करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

एसोचैम ने विलय और अधिग्रहण के लिए एकल स्टैंप ड्यूटी की वकालत की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग संगठन एसोचैम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा है कि विलय और अधिग्रहण के सौदों में 'एक राष्ट्र, एक स्टैंप ड्यूटी' के सिद्धांत पर यह शुल्क लिया जाए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद ऐसे सौदों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। एसोचैम ने वित्त मंत्री के समक्ष विलय और अधिग्रहण सौदों को आसान बनाने के लिए 'एक राष्ट्र, एक स्टैंप ड्यूटी' के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। उद्योग संगठन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्यों के स्तर पर उच्च कर लागत, आयकर प्रक्रियाओं के अनुपालन सहित अन्य मुद्दों का उल्लेख करते हुए एसोचैम ने सरकार और नियामकों के बीच बेहतर समन्वय की मांग की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विलय और अधिग्रहण लेनदेन दो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्टैंप ड्यूटी के अधीन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इन सौदों की प्रकृति अंतर-राज्यीय होती है। एसोचैम के प्रतिनिधि ने कहा कि क्या यह अनुचित नहीं है कि संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए दो बार स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि कानून के मूल सिद्धांतों में यह कहा गया है कि किसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है।

चीन से घटा भारत का आपसी व्यापार, अमेरिका के साथ बढ़ा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया, जो 2018-19 में 87.08 अरब डॉलर था। दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर भी 53.57 अरब डॉलर से घटकर 48.66 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन 2013-14 से 2017-18 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। चीन से पहले, यूएई देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया था।

आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना रहा, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था। अमेरिका उन चुनिंदा देशों में एक है, जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर बढ़कर 17.42 अरब डॉलर भारत के पक्ष में रहा । 2018-19 में अधिशेष 16.86 अरब डॉलर था।

चीनी सामान के बहिष्कार की मांग

चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी से देश में चीनी सामान के बहिष्कार

और वहां से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने की मांग उठी है। सरकार भी चीन पर आयात निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। जानकारों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे क्योंकि दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने में लगे हैं।

अमेरिका से बढ़ते आर्थिक संबंध

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में इकनोमिक्स के प्रफेसर विश्वजीत धर ने कहा कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ने का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा, अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी से भारतीय सामान की मांग है और हम इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। एक संतुलित व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में और मजबूती आएगी। लुधियाना के हैंड टूल्स एसोसिएशन के प्रेजिडेंट सुभाष चंद्र रल्हान ने कहा कि अमेरिका और भारत में चीन के लिए गुस्सा है और इससे दोनों देशों के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मौका है। उन्होंने कहा, चीन के खिलाफ गुस्से के कारण अमेरिका की कई कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। वे भारत जैसे देश में नए सप्लायर्स को खोज रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत से अमेरिकी निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा।

कोरोना वायरसः

बढ़ते संक्रमण के कारण फिर से लॉकडाउन की ओर भारत

फिर लॉकडाउन हुआ तो बढेगी उद्योगों की दिक्कत

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 29 हज़ार 429 नये मामले दर्ज किये गए हैं और कोविड-19 की वजह से 582 लोगों की मौत हुई है। सरकारी डेटा के अनुसार, भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के 9 लाख 36 हज़ार से ज़्यादा केस दर्ज किये जा चुके हैं। इनमें से 5 लाख 92 हज़ार से अधिक लोग संक्रमण के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. जबकि 3 लाख 19 हज़ार 840 मरीज़ों में अब भी संक्रमण के लक्षण हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि भारत में अब तक 24 हज़ार 309 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। बुधवार को अधिकारियों ने बताया कि भारत में कोविड-19 के मरीज़ों का रिकवरी रेट बढ़कर 63.20 प्रतिशत हो गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक़, भारत में इस महामारी से ठीक होने वालों और मरने वालों का अनुपात 96%:4% है।

कोरोना संक्रमितों की बढती संख्या से एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की चर्चा शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन किसी भी स्थिती में ठीक नही है। उद्योगों के नजरिए से लॉकडाउन से महामंदी का दौर आ जाएगा। जो स्थिती अभी थोडी संभली है उसमें भी गिरावट आएगी जो देश के हित में नही है। हालांकि इस मामलें केंद्र सरकार ने लॉकडाउन करने का निर्णय राज्य शासन पर छोडा है। राज्य शासन ने स्थानीय स्तर पर बनाई गई आपदा प्रबंधन समितियों को इसका निणर्य लेने की जिम्मेदारी दी है।

औद्योगिक संगठन भी लॉकडाउन के पक्ष में नही

कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण एवं बढते मामलों को लेकर प्रशासन चिंतित है और पुनः लॉकडाउन किये जाने पर विचार विमर्श हो रहा है। सभी का मानना है कि पुनः लॉकडाउन हुआ तो कई उद्योगों का भविष्य भी लॉकडाउन

हो जायेगा क्योकि बहुत मुश्किल से स्थिति 2 माह की विषम परिस्थिति से सुधार की ओर आई है ऐसे में पुनः लॉकडाउन होने से उद्योगों का भविष्य खतरे में पड जायेगा। कोविड-19 महामारी के चलते वर्तमान हालात निश्चित ही चिंताजनक है तथा इसे देखते हुए नागरिको के स्वास्थ एवं सुरक्षा कारणों से लॉकडाउन चर्चा है। फिर से लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे औद्योगिक क्षेत्रों को मुक्त रखा जाना आवश्यक होगा, औद्योगिक गतिविधियां चालू रखना होगी अन्यथा पुनः बंद की स्थिति में उद्योगो का भारी नुकसान होगा कई उद्योग तो अब बंद ही हो जाएगें।

अनलॉक होने के बाद अभी भी उद्योगों में 50 प्रतिशत उत्पादन कार्य ही आरंभ हो सका है तथा बडी मुश्किल से उत्पादन कार्य शुरू हुआ है। उद्योगों द्वारा श्रमिकों को बडे ही परिश्रम से बाहर से पुनः बुलाकर जैसे तैसे अपना उत्पादन कार्य आरंभ किया है। पुनः लॉकडाउन होने से श्रमिकों का पलायन होगा जो औद्योगिक दृष्टि से भारी क्षति पहुंचायेगा। उद्योग एक बार फिर बंद होने से लाखों का नुकसान होगा जिसमें कुटीर, सूक्ष्म व लघु श्रेणी उद्योगों का भविष्य खतरे में पड जायेगा। उद्योगों पर बैंक ब्याज, बिजली शुल्क श्रमिकों के वेतन आदि का भार आयेगा तथा दो माह पूर्व की स्थिति निर्मित होगी इससे उबरना कई उद्योगों के लिए कठिन होगा।

ऐसे कई उद्योग है जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते है उन्हें तो अनुमति मिल जाती है परंतु ऐसे कई उद्योग है जो आवश्यक वस्तुओं का निर्माण नही करते परंतु फिर भी 24 घंटे वहां उत्पादन कार्य किया जाता है ऐसे उद्योगों को भी इस बंदी से मुक्त रखा जाना आवश्यक होगा अन्यथा उनका भी कई गुना नुकसान होगा। औद्योगिक गतिविधियों के आरंभ होने से शासन के राजस्व में भी इजाफा हुआ है पुनः बंद की स्थिति होने से राजस्व में कमी होगी। दो माह की बंद की स्थिति के बाद उद्योगो ने गति पकडी है तथा उद्योगों में इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी कोई कोरोना पॉजिटीव केस नही मिला है और ना ही उद्योगों के कारण कोरोना फैला है। उद्योगों द्वारा समय समय पर जारी 'ासन प्रशासन के समस्त कोविड दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया है तथा अपने कारखानों में भी कराया है।

अल्कोहल वाले हैंड सैनिटइाइजर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा : एएआर

नयी दिल्ली। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने व्यवस्था दी है कि सभी अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। स्प्रिंगफील्ड इंडिया डिस्टिलरीज ने एएआर की गोवा पीठ में अपील कर कंपनी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सैनिटाइजर का वर्गीकरण करने को कहा था। कंपनी की दलील थी कि इस उत्पाद पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसके अलावा कंपनी ने यह भी पूछा था कि अब सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु है, तो क्या इसपर जीएसटी छूट मिलेगी। एएआर ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आवेदक द्वारा विनिर्मित हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित है। इसपर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। प्राधिकरण ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हालांकि हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन जीएसटी कानून में छूट वाली वस्तुओं की अलग सूची है। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह निष्कर्ष जीएसटी प्राधिकरण के हैंड सैनिटाइजर पर 18 प्रतिशत की कर दर के विचार के अनुरूप है। जैन ने कहा कि शुरुआत से ही हैंड सैनिटाइजर का वर्गीकरण बहस का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की मांग काफी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में कंपनियां सैनिटाइजर बाजार में कूद चुकी है। ऐसे में सरकार को बेवजह के विवाद से बचने के लिए इसपर एक चीजों को साफ करते हुए स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए।

आयकर विभाग ने नकद निकासियों पर टीडीएस दरों का पता लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई

नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि उसने बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों नॉन फाइलर्स के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है। इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अब बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है। बयान में कहा गया कि अभी तक इस सुविधा के तहत 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है। सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हैं।

सैनिटाइजर निर्माताओं ने जीएसटी खिलाफ खोला मोर्चा

कहा इसका वर्गीकरण डिसइंफेक्टेंट के तौर पर करना गलत

चंडीगढ़। एजेंसी

जीएसटी प्राधिकरण द्वारा जीएसटी के अनुचित वर्गीकरण का आरोप लगाए जाने पर सेनिटाइजर कंपनियों ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंपनियों का कहना है कि सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किए जाने और सेनिटाइजर की अधिकतम कीमत तय किए जाने के बावजूद उद्यमियों ने युद्ध स्तर पर हैंड सैनेटाइजर का उत्पादन किया। मगर जीएसटी प्राधिकरण उद्यमियों को कोरोना योद्धा के रूप में सममानित करने की बजाए टैक्स चोर साबित करने की कोशिश कर रहा है।

सेनिटाइजर कंपनियों के अनुसार हैंड सेनेटाइजर तैयार करने वाली कंपनियां ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत ड्रग लाइसेंस लेकर सेनिटाइजर बना रही हैं। सेनिटाइजर का वर्गीकरण 'मेडिसनल प्रेपरेशन', के तौर पर 'दी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955' के तहत किया गया है। इसी अधिनियम के अनुसार कंपनियां एक्साइज ड्यूटी अदा भी कर रही हैं। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद मेडिकामेंटस श्रेणी के तहत एचएसएन 3004 के अनुसार सभी कंपनियां सेनिटाइजर पर 12 प्रतिशत जीएसटी भी जमा करवा रही है। लेकिन अचानक जीएसटी प्राधिकरण ने हैंड सेनेटाइजर को एचएसएन 3808 के अधीन डिस्इनफेक्टेंट की श्रेणी में शामिल कर दिया। इस श्रेणी के उत्पादों पर 18 फीसदी जीएसटी निर्धारित किया गया है। ऐसे में जीएसटी प्राधिकरण ने सेनिटाइजर निर्माता कंपनियों को जीएसटी चोरी के नोटिस भी भेज दिए। कंपनियों का कहना है कि सभी कंपनियां उपभोक्ताओं से 12 फीसदी जीएसटी वसूल कर नियमानुसार सरकार को अदा कर रही हैं। ऐसे में जीएसटी चोरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। एजेंसी

पोत परिवहन मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया गोदी परिसर में आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। केंद्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि 'कोलकाता पोर्ट' के 'हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स' के पांच घाटों (जेटी) पर आधुनिक

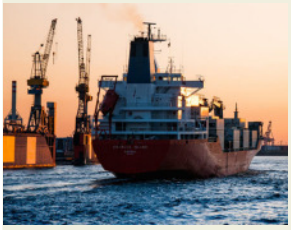

अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर किये। कोलकाता बंदरगाह देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन की आधुनिक सुविधा से पेट्रो-केमिकल उत्पादों की आवाजाही के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी। मौजूदा अग्निशमन सुविधा, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के रखरखाव के सन्दर्भ में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो रखरखाव की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। यह अग्निसुरक्षा के लिए वैश्विक मानकों के अनुपालन की दिशा में एक कदम है। हल्दिया डॉक पर निकट भविष्य में एलपीजी और एलएनजी कार्गो की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान है। कोलकाता बंदरगाह पर अत्याधुनिक अग्निशमन बुनियादी ढाँचा, ओआईएसडी-दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से पेट्रो-रसायन उत्पादों के प्रबंधन में मदद करेगा।

नए संसद भवन के लिये सात कंपनियों ने पात्रता पूर्व बोलियां लगायी

नयी दिल्ली। नए संसद भवन बनाने के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. समेत सात कंपनियों ने पात्रता पूर्व बालियां जमा की हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के रिकार्ड से यह पता चला है। सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि पात्रता पूर्व बोलियां मंगलवार दोपहर खोली गयी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ऑनलाइन निविदा पोर्टल के अनुसार कुल सात कंपनियों ने पात्रता पूर्व बोलियां जमा की हैं। ये कंपनियां हैं... टाटा प्रोजेक्ट लि., लार्सन एंड टूब्रो लि., आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लि., एनसीसी लि., शपूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लि., उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. और पीएसपी प्रोजेक्ट्स लि.। एजेंसी के पात्रता पूर्व बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा संसद भवन के पास नई इमारत बनायी जाएगी। इसके 21 महीने में पूरा होने का अनुमान है और इस 889 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है। केंद्र रकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि नई इमारत का निर्माण 'पार्लियामेंट हाउस एस्टेट' की भूखंड संख्या 118 पर होगा।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने NPA को लेकर जताई चिंता

बैंकों को कैपिटल बफर करने का निर्देश

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को सचेत किया कि कोविड19 महामारी के कारण बैंकों के ऋण में तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन ऐंड डिमांड अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, ऐसे में अर्थव्यवस्था की अगले कुछ वर्ष की संभावनाओं के बारे में अनिश्चित बनी हुई है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था। यह विभिन्न चरणों में आगे बढ़ाया जाता रहा और मई की शुरुआत से इसकी पाबंदियों में ढील दी जाने लगी।

लॉकडाउन का परिणाम हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन और लोगों का खर्च बाधित हो गया। जून तिमाही के लिये सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का अनुमान भी इस कारण कम कर दिया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गयी है। दास ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और निजी बैंकों दोनों के लिए री-कैपिटलाइजेशन स्कीम जरूरी हो जाती है।

विकास दर में तेजी लाने पर काम

उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन पर महामारी के पर्याप्त प्रभाव के बावजूद, देश की वित्तीय

प्रणाली सहित सभी भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार बिना किसी बाधा के काम कर रहे हैं। दास ने कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील दिये जाने के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के संकेत देने लगी है। उन्होंने कहा कि अभी के समय की जरूरत भरोसे को फिर से बहाल करना, वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करना, वृद्धि दर को तेज करना और मजबूत वापसी करना है।

अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही है

दास ने कहा, 'लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दिये जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था अब सामान्य स्थिति की ओर लौटने के संकेत देने लगी है।' उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों और उद्योगों ने संकट के समय बेहतर प्रतिक्रिया दी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के पूरी तरह से बहाल होने और मांग की स्थिति सामान्य होने में कितना समय लगेगा, यह अभी अनिश्चित है। यह भी अनिश्चित है कि यह महामारी हमारी संभावित वृद्धि पर किस तरह का असर छोड़ती है।

फाइनैंशल स्टैबिलिटी पर रिजर्व बैंक की नजर

दास ने कहा, 'रिजर्व बैंक फाइनैंशल स्टैबिलिटी के खतरों के बदलते स्वरूप का लगातार आकलन कर रहा है और फाइनैंशल स्टैबिलिटी का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये निगरानी की रूपरेखा को उन्नत बना रहा है।' गवर्नर ने कहा कि बैंकों तथा वित्तीय बाजार की इकाइयों को सतर्क रहना होगा और उन्हें संचालन, विश्वास कायम रखने वाली प्रणालियों तथा जोखिम के संबंध में अपनी क्षमताओं को उन्नत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपना कंपनी संचालन सुधारना होगा, जोखिम प्रबंधन को तीक्ष्ण बनाना होगा और स्थिति उत्पन्न होने की प्रतीक्षा किये बिना अनुमान के आधार पर पूंजी जुटानी होगी।

रत्न, आभूषण निर्यात जून में 34.72 प्रतिशत गिरा

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोविड-19 संकट के चलते वैश्विक स्तर पर गिरी मांग से देश का रत्न और आभूषण निर्यात जून में 34.72 प्रतिशत गिरकर 1.64 अरब डॉलर (करीब 12,333 करोड़ रुपये) रह गया। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने यह जानकारी दी। पिछले साल जून में देश का रत्न-आभूषण निर्यात जून में 2.52 अरब डॉलर यानी 18,951 करोड़ रुपये का था। देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है। हाथ की कारीगरी के चलते यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। जीजेईपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह ने से कहा, "कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद से कई देशों ने विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक नरमी आने के चलते रत्न-आभूषण की मांग और निर्यात में लगातार कमी आ रही है। हालांकि चीन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में फिर से मांग सुधर रही है।" चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निर्यात 54.79 प्रतिशत घटकर 2.75 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में यह आंकड़ा 6.07 अरब डॉलर था। इस दौरान सोने के आभूषणों का निर्यात 79 प्रतिशत टूटकर 32.12 करोड़ डॉलर रहा। जबकि रंगीन रत्नों के निर्यात में 80.56 प्रतिशत की गिरावट रही। हालांकि चांदी के आभूषणों का निर्यात समीक्षावधि में बढ़कर 32.46 करोड़ डॉलर का रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 16.8 करोड़ डॉलर था। आलोच्य तिमाही में देश का रत्न और आभूषण का आयात 74.81 प्रतिशत गिरकर 91.51 करोड़ डॉलर रह गया। जबकि बिना पॉलिश हीरे का आयात 82.7 प्रतिशत घटकर 48.16 करोड़ डॉलर रहा। भाषा

इनकम टैक्स की ये छूट न मिलेगी दोबारा, 30 सितंबर तक निपटा दें यह काम

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग ने सोमवार को उन करदाताओं को एकबारगी छूट दी है जिन्होंने आकलन वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए कर रिटर्न का अबतक सत्यापन नहीं किया है। विभाग ने 30 सितंबर, 2020 तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। कोई करदाता बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अगर आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरता है, उसे उसका सत्यापन आधार 'वन टाइप पासवर्ड' या ई-फाइलिंग खाते पर नेट बैंकिंग के जरिये अथवा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) या आईटीआर-5 की फार्म पर हस्ताक्षर कर उसे सीपीसी बेंगलुरू भेजना होता है। उसे यह सब

आईटीआर अपलोड होने के 120 दिनों के भीतर करना होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे गए बड़ी संख्या में आईटीआर आकर रिटर्न अभी भी लंबित पड़े हैं। इसका कारण आईटीआर-5 सत्यापन फार्म संबंधित करदाताओं द्वारा 'सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी बेंगलुरू नहीं भेजना है। आदेश के अनुसार समय पर आईटीआर-5 नहीं जमा करने से रिटर्न को 'नहीं भरा हुआ' यानी अवैध घोषित कर दिया जाता है। इससे जुड़ी शिकायतों का एकबारगी समाधान के इरादे से सीबीटीडी ने आकलन वर्ष 2015-16, 2016-17, 2018-19 और 2019-20 के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए कर रिटर्न के सत्यापन की अनुमति दी है।

30 सितंबर तक सत्यापन जरूरी

इसके तहत या तो आईटी-5 फार्म पर दस्तखत कर उसे सीपीसी बेंगलुरू भेजना होगा या फिर ईवीसी/ओटीपी के जरिए इसका सत्यापन किया जा सकता है। इस प्रकार के सत्यापन को 30 सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना जरूरी है। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें इस दौरान आयकर विभाग ने रिटर्न को "नहीं भरा हुआ' घोषित किए जाने के बाद संबंधित करदाताओं के कर रिटर्न भरना सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत पहले से कोई कदम उठाया है।

क्यों अटक जाता है रिफंड

नांगियां एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार शैलेष कुमार ने कहा कि कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया नहीं होने पर आईटीआर को अवैध करार दिया जाता है। इसलिए अगर कोई कर रिफंड बनता है या फिर कोई दावा है, वह भी अटक जाता है। कुमार ने कहा, 'इस आदेश के जरिए सरकार ने न केवल करदाताओं को पिछले रिटर्न के सत्यापन के लिये 30 सितंबर तक का समय दिया है बल्कि 31 दिसंबर तक 2020 तक उसके निपटान की भी अनुमति दी है। इससे उन करदाताओं को लाभ होगा, जिन्होंने किसी कारण से पहले के आईटीआर का सत्यापन नहीं करवा पाए।'

EPFO से जुड़े लंबित मामलों की होगी ऑनलाइन सुनवाई, हजारों उपभोक्ताओं को फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार कोरोना संकट के बीच भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों को राहत देने पर विचार कर रही है। देश में ईपीएफओ से जुड़े हजारों मामले लंबित हैं, कोरोना महामारी की वजह से इन मामलों की नियमित सुनवाई नहीं हो रही है पीएफ और ईपीएफ निकासी जैसे कामों में देरी हो रही है।

इन लंबित मामलों की नियमित सुनवाई के लिए सरकार मामलों की ऑनलाइन सुनवाई कराने पर विचार कर रही है, इसके लिए ई-कोर्ट लगाए जाएंगे। हरियाणा के करनाल में ई-प्रोसेसिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। अगर श्रम मंत्रालय से जल्द मंजूरी मिल गई तो अनलॉक

के दौरान ही ईपीएफ के हजारों कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। कोर्ट में तारीख ना मिलने या फिर अधिकारियों के पास समय की कमी होने की वजह से मामले अटक जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ई-सुनवाई के सार्थक परिणाम हैं और इससे ग्राहकों को फायदा मिलेगा। देश में साल 2010 के बाद से ईपीएफ के अभीतक 68,000 मामले लंबित हैं।

कोरोना काल में ग्राहकों को मिलेगा इस सुविधा का फायदा

कोरोना के बीच सुनवाई के लिए ईपीएफओ कोर्ट नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से लंबित मामले और बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर दो साल पहले तैयार हो गया था लेकिन प्रभावी नहीं था। ई-कोर्ट की वजह से सुनवाई के लिए किसी को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंपनी के वकील, विभाग के निरीक्षक और अन्य सभी अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई करेंगे। करनाल में टेस्टिंग के बाद उम्मीद है जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 तक 13.3 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी : एनजीओ

नयी दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 तक करीब 13.3 करोड़ नौकरियां उपलब्ध होंगी, जिनमें मानव प्रयास, मशीनें और एल्गोरिदम से संबंधित नौकरियां शामिल हैं। एक गैर लाभकारी संगठन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसने साथ ही भारत में युवाओं के लिए डिजिटल और अंग्रेजी साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। संगठन ने कहा कि अकादमिक स्तर पर जो तैयार किया जा रहा है और इंडस्ट्री जो चाहती है, उसमें काफी अंतर है। ऐसे में यह बेहद आवश्यक है कि युवाओं को प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन का ज्ञान, हरित ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से कौशल प्रदान किया जाए। ये टिप्पणियां गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) वाधवानी फाउंडेशन की ओर से विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) की पूर्व संध्या पर की गईं। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवा पीढ़ी के बीच कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, वर्ष 2016 में 25.9 करोड़ युवा ऐसे थे जो रोजगार, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण में शामिल नहीं थे। यह संख्या 2019 तक बढ़कर 26.7 करोड़ हो गई और 2021 तक बढ़कर 27.3 करोड़ होने का अनुमान है।

एमसीएक्स ने सेबी से आलू वायदा फिर शुरू करने की अनुमति मांगी

मुंबई। एजेंसी

जिंस कारोबार के लिये मंच उपलब्ध कराने वाले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने कहा है कि उसने आलू वायदा कारोबार फिर से शुरू करने के लिये पूंजी बाजार नियामक सेबी से अनुमति मांगी है। कृषि क्षेत्र के सुधारों पर आयोजित वेबिनार में एमसीएक्स के व्यवसाय विकास के प्रमुख रिषी नैथाणी ने कहा, ''आम इस्तेमाल वाले दलहन और चीनी जैसे संवेदनशील जिंस में जोखिम से सुरक्षा की जरूरत है .. हम जल्द ही आलू में वायदा कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं।'' वह कृषि वायदा कारोबार को बढ़ाने की उद्योगों की मांग पर अपनी बात रख रहे थे।

उन्होंने कहा कि एक्सचेंज ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आलू वायदा अनुबंध फिर से शुरू करने के लिये अनुमति मांगी है। इसके लिये आवेदन किया गया है। उन्होंने कहा एमसीएक्स में आल वायदा अनुबंध काफी सफल रहा है लेकिन कुछ समय बाद इसमें तरलता समाप्त हो गई। इसकी वजह से तत्कालीन जिंस बाजार वायदा कारोबार के नियामक वायदा बाजार आयोग ने एमसीएक्स को सितंबर 2014 में यह कारोबार बंद करने को कहा। कृषि सुधारों पर वेबिनार का आयोजन एमसीएक्स और इंडियन मर्चेंट्स चैंबर ने मिलकर किया था। इस दौरान खाद्य व्यवसाय क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आईटीसी ने कई जिंसों में मूल्य जोखिम से बचने के लिये वायदा कारोबार शुरू करने पर जोर दिया। उसने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कच्चे तेल के दाम 70 प्रतिशत गिर गये, पॉम तेल 30 प्रतिशत सस्ता हो गया। मक्का, गेहूं और आलू के दाम में काफी उतार - चढ़ाव देखा गया जिससे रोजमर्रा के उत्पाद तेयार करने वाली एफएमसीजी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा।पश्चिम बंगाल में ताड़केश्वर, दिल्ली, आगरा आलू के बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में आलू के बड़े भंडारगृह की सुविधायें मौजूद हैं। घरेलू और बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों के लिये ठेके पर खेती कराने के मामले में ये भंडारगृह काफी महत्वपूर्ण हो गये हैं।

कोरोना की मार से विकराल हो सकती है एनपीए की समस्याः राजन

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि अगले छह महीने में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए (NPA) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि समस्या को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए, उतना अच्छा होगा। कोविड-19 और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनमें से कई कर्ज की किस्त लौटाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

राजन ने 'नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड एकोनॉमिक रिसर्च' (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित 'इंडिया पॉलिसी फोरम'2020 के एक सत्र में कहा, 'अगर हम वाकई में एनपीए के वास्तविक स्तर को पहचाने तो अगले छह महीने में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का स्तर काफी अप्रत्याशित होने जा रहा है। हम समस्या में हैं और जितनी जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतना बेहतर होगा। क्योंकि हमें वाकई में इस समस्या से निपटने की जरूरत है।' मंगलवार को प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में आर्थिक सुधारों पर एक लेख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जनधन खातों की सफलता की बात कही गई है लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों की राय इससे अलग हैं।

कृषि क्षेत्र से उम्मीद

राजन ने कहा, 'हमें अभी भी लक्षित लोगों को लाभ अंतरण करने में कठिनाई हो रही है। लोग अभी भी सार्वभौमिकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लक्ष्य नहीं कर सकते। (जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजय जोशी ने रेखांकित किया है)। जनधन उस रूप से काम नहीं किया जैसा कि इसका प्रचार-प्रसार किया गया।' हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सकारात्मक चीज कृषि क्षेत्र है जो वास्तव में अच्छा कर रहा है। राजन ने कहा, 'निश्चित रूप से सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया है। इन सुधारों की लंबे समय से बात हो रही थी। उसके सही तरीके से क्रियान्वयन होने से अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को लाभ होगा।'

देश में हवाई यात्रा में 2020 में आ सकती है 49 प्रतिशत गिरावट : आईएटीए

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 संकट और उससे जुड़े लॉकडाउन ने भारतीय विमानन क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। विमानन कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय संगठन आईएटीए का अनुमान है कि 2020 में देश में हवाई यात्रियों की संख्या में 49 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने सोमवार को कहा कि 2020 में भारतीय विमानन कंपनियों की आय पिछले साल के मुकाबले 11.61 अरब डॉलर कम रहेगी। रपट में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हवाई यात्रा की मांग में 53.8 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। आईएटीए के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (एशिया-प्रशांत) कॉनरैड क्लिफोर्ड ने कहा, '' विमानन क्षेत्र के इतिहास में यह सबसे खराब साल है और विमानन कंपनियां किसी तरह अस्तित्व बचाने में लगी हैं। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विमानन कंपनियों को 29 अरब डॉलर का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यह प्रति यात्री 30.09 डॉलर का नुकसान है।'' क्लिफोर्ड ने कहा, '' 2019 के स्तर पर वापस आने में विमानन उद्योग को कुछ साल लगेंगे।'' भारत ने 24 मार्च से हुए लॉकडाउन के बाद देश में लगभग दो महीने बाद 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानों को दोबारा शुरू कर दिया । हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर देश में अब भी प्रतिबंध है।

देशी तेलों पर सस्ते आयातित तेलों की मार घरेलू तेल उद्योग में गतिविधियां पड़ी सुस्त

नयी दिल्ली। एजेंसी

विदेशों से पाम तेल के अलावा सोयाबीन डीगम जैसे सस्ते तेलों का आयात बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों, मूंगफली और सोयाबीन (तिलहन फसल) के अलावा मूंगफली तेल जैसे घरेलू तेल तिलहनों में गिरावट दर्ज हुई। वहीं स्थानीय मंडी और विदेशों में मांग बढ़ने से आयातित सोयाबीन और पाम तेल कीमतों में सुधार रहा। बाजार सूत्रों ने कहा कि सरसों किसानों द्वारा सस्ते कीमत पर अपनी ऊपज को नहीं बेचने से सरसों दाना, सरसों दादरी, सरसों पक्की एवं कच्ची घानी तेल कीमतें पूर्वस्तर पर टिकीं हुई हैं। वहीं घरेलू तेल के मुकाबले सस्ता पड़ने से कच्चा पॉम तेल, पामोलीन, सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम तेल में सुधार दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि वायदा कारोबार में सोयाबीन के अक्टूबर डिलीवरी वाले अनुबंध का भाव 3,620 रुपये क्विन्टल (वारदाना एवं मंडी शुल्क व अन्य खर्चे समेत) चल रहा है जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3,880 रुपये क्विन्टल (सारे खर्च अलग से) तय किया गया है। हाजिर मंडी में इसका भाव एमएसपी से लगभग सात प्रतिशत नीचे चल रहा है। घरेलू तेलों के मुकाबाले सस्ता पड़ने से निकट भविष्य में सोयाबीन डीगम और पाम तेल का आयात तेजी से बढ़ने की संभावना है। विदेशों में इनके उत्पादन में भारी वृद्धि होने की भी संभावना है। ऐसे में घरेलू तेल तिलहन उद्योग के समक्ष संकट खड़ा हो सकता है। किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर भी सवाल उठ सकते हैं। व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने और घरेलू तेल तिलहन उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने के लिये खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर संतुलन बिठाना चाहिये। सोयाबीन की नई फसल भी आने वाली है और पिछला स्टॉक भी बचा है ऊपर से आयात भी बढ़ रहा है ऐसे में घरेलू उत्पादकों को भारी नुकसान की आशंका परेशान किये हुये है।

हरियाली अमावस्या

20 साल बाद तीसरे सावन सोमवार पर बन रहा दुर्लभ सर्वार्थसिद्धि योग

सावन के तीसरे सोमवार पर ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। 20 जुलाई को हरियाली और सोमवती अमावस्या के साथ पुनर्वसु नक्षत्र, हर्षण योग, चतुष्पद करण, सर्वार्थसिद्धि योग तीसरे श्रावण सोमवार को बेहद खास बना रहा है। 20 साल बाद हरियाली अमावस्या पर सोमवती का संयोग बन रहा है। 20 साल पहले शुक्रवार 31 जुलाई 2000 में सोमवती अमावस्या थी। इसके बाद 2004 में सावन महीने को पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया गया था। उस साल दो बार सावन महीना पड़ा था। दूसरे सावन महीने में सोमवती अमावस्या का संयोग बना था। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि हरियाली अमावस्या के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के बाद रात्रि में 9.47 बजे से पुष्य नक्षत्र रहेगा। सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थानों, नदियों, जलाशयों में स्नान करना और दान-दर्शन का विशेष महत्व है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ऐसा संभव नहीं है इसलिए लोग पवित्र

जल का मिश्रण करके घर पर स्नानदान करें। इससे भी गंगा में स्नान के समान पुण्य की प्राप्ति होगी।

इस बार रवियोग में मनेगी नागपंचमी

नागपंचमी का पर्व 25 जुलाई को श्रावण शुक्ल पंचमी को रवियोग में मनाया जाएगा। रवि योग में नागदेवता की पूजा आराधना करने से कर्ज मुक्ति, स्वास्थ्य और सर्जरी के कार्य का बेहतर लाभ मिलता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषाचार्य एचसी जैन के अनुसार इस बार श्रावण शुल पंचमी शनिवार को है, साथ ही चंद्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर 2 बजकर 17 मिनट से पूरे समय रहेगा। इसके चलते रवियोग का निर्माण हो रहा है। जिसकी कुंडली में राहु, केतु के साथ सूर्य बैठा हो, अथवा ग्रहण योग, कर्ज योग आदि होते हैं तो वह नागपंचमी पर रवियोग में पूजा आराधना कर नाग नागिन के जोड़े को जंगल में सपेरों से मुक्त कराएं।

नागों का है भगवानों से गहरा नाता

सनातनधर्म में सांपों का भगवानों से गहरा नाता बताया गया है। भगवान शिव के गले की नागदेवता शोभा बढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की शेषशैया भी नाग देवता की है। सावन मास के देवता भगवान शिव माने जाते हैं। इस समय वर्षा के कारण जमीन के अंदर बिलों में रहने वाले सांप भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलकर आने वाले नाग किसी का अहित नहीं करें अथवा इंसानों द्वारा नागों का अहित नहीं हो, इसके लिए भी नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आमजन नागदेवता की पूजा आराधना करते हैं, जिससे उनके मन भी नागों के प्रति भक्तिभाव जागृत होता है।

ज्योतिष में है महत्व

नागपंचमी में धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ ही ज्योतिष में भी नागपंचमी का महत्व है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में योगों के साथ दोषों को भी देखा जाता है। इसमें कालसर्प दोष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कालसर्प दोष के साथ ग्रहण दोष, श्राप दोष, राहु, केतु की पीड़ा के लिए भी ज्योतिषाचार्य हमेशा नागपंचमी पर नागदेवता की पूजा के साथ दान दक्षिणा का सर्वाधिक महत्व मानते हैं।

कुंवारी कन्याएं करती हैं मनचाहे वर के लिए हरियाली अमावस्या व्रत

श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। भगवान शिव-पार्वती के साथ पितरों की भी पूजा होती है। मां पार्वती की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिल सकता है। ऐसी मान्यता पुराने समय से चली आ रही है। विवाहित महिलाएं भी इस तिथि पर व्रत करती हैं और देवी मां की पूजा करती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। हरियाली अमावस्या पर अच्छी खेती के लिए किसान हल, हंसिया की पूजा भी करते हैं। किसानों की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या पर किसी एकांत स्थान के जलाशय में

जाकर स्नान-दान, गरीबों को भोजन कराने से पितृगण प्रसन्न होते हैं।

अमावस्या पर शिव-पार्वती पूजा का महत्व

अमावस्या तिथि पर शिवजी के साथ ही देवी पार्वती का पूजन अवश्य करें। पूजा में ऊं उमामहेश्वराभ्यां नमः मंत्र का जप करें। माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर बनाना चाहिए।

पितरों की याद में किया जा सकता है पौधरोपण

इस तिथि पर पितरों के लिए पूजा-पाठ और श्राद्ध-तर्पण किया जाता है। पितरों को चढ़ाने वाले फूल सेवंती, अगस्त, तुलसी, भृंगराज, शमी, आंवला, श्वेत पुष्प आदि के पौधे लगा सकते हैं। इनका रोपण करें और आगामी श्राद्धपक्ष में पितरों को अर्पित करें। इससे घर-परिवार में सुख बढ़ेगा। पौधों के रूप में पूर्वजों की याद भी बनी रहेगी।

चार ग्रह रहेंगे अपनी राशि में

शुभग्रह योगों में बुध, गुरु, शुक्र, शनि चार ग्रह अपनी राशि में रहेंगे। वहीं, राहु पर मंगल की दृष्टि से अनावृष्टियोग है। वस्तुओं के दाम में उछाल रहेगा। पेट्रोल एवं तेल के भाव में वृद्धि का दुर्योग है। आर्थिक हानि से अनेक कंपनियां तंग रहेंगी। भ्रष्टाचार में वृद्धि के संकेत हैं। धार्मिक अभ्युदय के लक्षण हैं। विदेश नीति प्रबल होगी।

इस नियम से लगायें पौधे, रहेंगे सभी परेशानियों से दूर

■पौधारोपण हेतु उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी और मूल नक्षत्र अत्यंत शुभ होते हैं। इनमें रोपे गए पौधों का रोपण निष्फल नहीं होता है।

■जिन वृक्षों में फल लगना बंद हो गए हो या कम लगते हों उन्हें कुलथी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले जल से सींचना चाहिए।

■जिस वृक्ष के तने के चारों ओर सूअर की हड्डी का एक-एक टुकड़ा गाड़ दिया जाता है, वह सदैव हरा रहता है, कभी सूखता नहीं है।

■जिस घर की सीमा में निर्गुंडी का पौधा होता है, वहाँ हमेशा अमन-चैन रहता है। इसी प्रकार अंगूर, पनस, पाकड़ तथा महुआ के पौधों का भी घर की सीमा में रोपण शुभ होता है।

■आमलक को लगाने वाले की जमीन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। फिर चाहे उस व्यक्ति के द्वारा इस पौधे का रोपण कहीं भी क्यों न किया जाए।

■चन्द्रमा की पीड़ा हरण हेतु गूलर का पौधा लगाना चाहिए।

■ घर के पूर्व में बरगद का, पश्चिम में पीपल का, उत्तर में पाकड़ का तथा दक्षिण में गूलर का वृक्ष होना शुभ होता है। इसके विपरीत पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद और घर के उत्तर में गूलर का वृक्ष अशुभ माना गया है।

■जिस व्यक्ति के घर में बिल्व का एक वृक्ष लगा होता है, उसके यहां साक्षात लक्ष्मी का वास रहता है।

■घर की सीमा में कदली (केला), बदरी (बेर) एवं बाँझ अनार के वृक्ष होने से वहां के बच्चों को कष्ट उठाना पड़ता है।

■घर में रेगिस्तानी पौधों का होना शत्रु बाधा, अशांति एवं धनहानि का कारक होता है। कैक्टस के पौधे इसी श्रेणी में आते हैं।

■जो व्यक्ति दो बड़ के वृक्षों का रोपण करता है उसके अनेक पापों का शमन होता है। यह वृक्ष किसी खुले मैदान में ही रोपण करें।

■जो व्यक्ति पलाश के वृक्ष का रोपण करते हैं उन्हें उत्तम संतान और सुख देने वाले पुत्र अवश्य ही प्राप्त होते हैं, किंतु पलाश का वृक्ष घर की सीमा में न हो।

■किसी भी कारण से वृक्ष के काटने पर दूसरे 10 वृक्षों का रोपण और पालन करने वाला उसके पाप से मुक्त हो सकता है।

दान करने का सही समय

■शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन हर समय और हर किसी को दिया गया दान लाभदायी नहीं होता है। कुछ समय ऐसे हैं जब किसी खास चीज का किया गया दान बड़ा ही फायदेमंद होता है।

■लाल किताब के अनुसार शनिवार के दिन घर से कहीं जाते समय रास्ते में अगर कोई भिखारी दिख जाए तो उसे कुछ धातु की मुद्राएं देनी चाहिए। इससे शनि का शुभ प्रभाव बढ़ता है। शनि के कारण जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिवार को शाम के समय तिल, तेल, कंबल का दान शनि की पीड़ा कम करता है।

■शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन जरुरतमंद बच्चों को किताब कॉपी और कलम का दान करना शुभ फलदायी होता है। व्यापारी भी कारोबार में लाभ के लिए बुधवार को इन चीजों का दान कर सकते हैं।

■ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इससे बुध का शुभ फल प्राप्त होता है। सुबह उठते ही अगर कोई भिखारी द्वार पर आकर भिक्षा मांगे तो उसे आटा दान करना चाहिए। इसके अलाव अगर आप रोटी बनाने के लिए आटा गूथ रहे हों और कोई भिखारी भिक्षा मांगने आ जाए तो उसे आदर सहित आटा देना चाहिए। इस समय किया गया आटा दान जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा करता है। माना जाता है कि इससे परिवार के किसी सदस्य पर आने वाला संकट टल जाता है।

लॉकडाउनः गाड़ियों की बिक्री में 45 फीसदी तक गिरावट की आशंका, GST में छूट की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट की आशंका है. वाहन निर्माताओं का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण गाड़ियों की बिक्री में 26 से 45 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। व्हेकिल उद्योग का कहना है कि गाड़ियों की बिक्री को 2018-19 के स्तर पर पहुंचने में भी कम से कम तीन-चार साल लग जाएंगे। वाहन मार्केट में किसी नए निवेश की उम्मीद नहीं है क्योंकि पहले से ही बनी गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही है।

बिक्री में हल्की बढ़ोतरी, लेकिन पिछले साल के स्तर से काफी कम

गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट को देखते हुए इंडस्ट्री ने सरकार से जीएसटी में कटौती की मांग की है. हाल के दिनों में टू-व्हीलर्स समेत गाड़ियों के कुछ सेगमेंट की बिक्री में इजाफा दिखा है। लेकिन वाहन इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहले से बुक की गाड़ियों की डिलीवरी से दिख रहा है। चूंकि अप्रैल में पूरी तरह शटडाउन था इसलिए मई में गाड़ियों की बिक्री होने से मांग बढ़ी हुई दिख रही है। मई की तुलना में जून में वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। मारुति, हुंडई, हीरो मोटकॉर्प, टोयोटा और किया की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी तक यह स्तर पिछले साल जून के स्तर तक नहीं पहुंचा है। गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट को देखते हुए ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से जीएसटी दर घटाने की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि अलग-अलग व्हेकिल कैटेगरी के लिए जीएसटी अलग-अलग है। यह रेंज 28 से 60 फीसदी तक है. ऐसे में कंपनियां सिर्फ तीन से नौ फीसदी तक ही मुनाफा कमा पाती हैं। कॉमर्शियल व्हेकिल में कंपनियों का मुनाफा 3 फीसदी तक होता है। टू-व्हीलर्स में 9 फीसदी तक मुनाफा होता है. पैसेंजर व्हेकिल्स में 5 से 6 फीसदी तक मुनाफा कमाया जाता है। कंपनियों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से सुरक्षा मानकों का पालन करने की वजह से फैक्टरियों में उनकी लागत बढ़ गई है। इस वजह से अब वह गाड़ियों पर ज्यादा छूट भी नहीं दे पा रहे हैं. इसलिए सरकार से जीएसटी घटाने की मांग की जा रही है।

डिफेंस के लिए महिंद्रा ने उतारा बख्तरबंद वाहन

माओवादी, आतंकियों के मंसूबे होंगे ध्वस्त

नई दिल्ली। एजेंसी

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने डिफेंस सेक्टर में कदम आगे बढ़ाते हुए एक अत्याधुनिक और हाईटेक बख्तरबंद वाहन लॉन्च किया है जो सैन्य, अर्द्धसैनिक बलों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी खासियत यह है कि यह माओवादी या अन्य तरह के आतंकियों द्वारा बिछाए जाने वाले लैंड माइंस से भी जवानों को सुरक्षित रखेगा। कंपनी के मुताबिक, इसे जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्च के बारे में बताते हुए महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट में इसे 'मीन मशीन' यानी बहुत ताकतवर वाहन बताया।

क्या है खासियत

यह वाहन माइन रोधी है यानी घात लगाकर बिछाए गए लैंड माइंस से सुरक्षित रहता है. इसे महिंद्रा डिफेंस के द्वारा ही डिजाइन और तैयार किया गया है, जिसे निर्यात भी किया जाएगा। एसपी शुक्ला ने बताया कि इसे जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक अभियानों में लगाया जाएगा। यह ट्रक जैसा भारी बख्तरबंद वाहन है। यही नही इसमें कई ऐसी चेक करने वाली भुजाएं भी लगी हैं जो सड़कों के किनारे पड़े विस्फोटक डिवाइस (IEDs) को हटा या उठा सकती हैं। यह वाहन माओवादी या अन्य आतंकियों द्वारा बिछाए जाने वाले लैंड माइंस विस्फोटकों से सुरक्षा बलों को बचाएगा।

क्या कहा आनंद महिंद्रा ने

महिंद्रा डिफेंस के एग्जीक्यूटिव एसपी शुक्ला ने इस वाहन का फोटो ट्वीट किया था, जिसे आनंद महिंद्रा ने भी रीट्वीट किया है। आनंद महिंद्रा ने कहा, 'यह किसी मीन मशीन जैसा लगता है। प्रकाश शुक्ला इसमें महिंद्रा डिफेंस की वास्तवकि भावना समाहित है, जो शांति रक्षकों को सुरक्षित रखने के बारे में है. उन्होंने मजाक में कहा कि वह बख्तरबंद वाहन मुंबई की ट्रैफिक के लिए भी परफेक्ट है, लेकिन यह अलग बात है कि आम सड़कों पर ऐसा वाहन चलाना अवैध है।

रक्षा उत्पादन क्षेत्र में स्वतः स्वीकृत मार्ग से 74 प्रतिशत एफडीआई के नियम की मंजूरी की तैयारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) स्वतः स्वीकृत मार्ग से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी के लिये जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क करेगा। इस पहल का मकसद क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना है। सूत्रों ने कहा कि डीपीआईआईटी ने रक्षा मंत्रालय के साथ मामले पर चर्चा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा के दौरान स्वतः स्वीकृत मार्ग से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक एफडीआई की मंजूरी देने की घोषणा की थी। मौजूदा एफडीआई नीति के तहत रक्षा उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी है। इसमें 49 प्रतिशत स्वतः स्वीकृत मार्ग से जबकि उसके ऊपर सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। सरकार ने जुलाई 2018 में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को उदार बनाते हुए 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वतः स्वीकृत मार्ग से मंजूरी दी थी। डीपीआईआईटी के आंकड़े के अनुसार देश के रक्षा उद्योग ने अप्रैल 2000 से मार्च 2020 के दौरान 95.2 लाख डॉलर (56.88 करोड़ रुपये) का एफडीआई प्राप्त किया।

गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से पहले देनी होगी FASTag की डिटेल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने पूरे देश में नए वाहनों के पंजीकरण से पहले और राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते वक्त फास्टैग (FASTag) विवरण लेने का फैसला किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी से नए वाहनों के पंजीकरण से पहले और राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते वक्त फास्टैग (FASTag) विवरण लेना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने एनआईसी को लिखे एक पत्र में कहा है कि वाहन (वीएएचएएन) पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) को पूरी तरह जोड़ दिया गया है और यह 14 मई को एपीआई के साथ लाइव हुआ है। वाहन प्रणाली अब वीआईएन/ वीआरएन के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रही है। इस पत्र की कॉपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है।

क्यों जरूरी है फास्टैग

इस प्रकार, मंत्रालय ने नए वाहनों का पंजीकरण करते वक्त और राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने को कहा है। एम और एन श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बैंक खाते के साथ जोड़ने या उन्हें सक्रिय किए जाने से नागरिक बच रहे थे जिसकी अब जांच की जाएगी।

रेलवे का एक और कारनामा, पहली बार विदेश भेजी स्पेशल पार्सल ट्रेन

फास्टैग लगाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा को पार करने वाले वाहन फास्टैग भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करें और नकद भुगतान से बचें। फास्टैग का यह उपयोग और प्रचार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर कोविड के प्रसार की संभावनाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा। इस योजना पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर, 2017 में राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। मई 2020 की शुरुआत तक देश भर में कुल 1.68 करोड़ FASTags जारी किए गए हैं।

भारत, अमेरिका की शीर्ष कंम्पनियों ने पारस्परिक निवेश अवसर बढ़ाने के उपायों पर की चर्चा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत और अमेरिका के शीर्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) ने मंगलवार को स्वास्थ्य, एयरोस्पेस, रक्षा, बुनियादी ढांचा, आईसीटी और वित्तीय सेवा समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। भारत-अमेरिका सीईओ मंच के टेलीफोन के जरिये आयोजित सम्मेलन में यह चर्चा की गयी। मंच की सह-अध्यक्षता टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष एवं सीईओ जेम्स टेसलेट ने की।बयान के अनुसार चंद्रशेखरन ने मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्तों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत को रेखांकित किया और अमेरिकी सरकार से भारत के मानव संसाधन के योगदान को स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसी प्रतिभाओं को बेरोक-टोक आवाजाही की जरूरत बतायी। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुशल कामगारों के लिये एच-1बी वीजा के आधार पर साल की शेष अवधि के लिये विदेशी कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी किया। साथ ही उन्होंने कंपनी के भीतर स्थानांतरित प्रबंधकों और विशेष योग्यता रखनेवाले कर्मचारियों के लिये एल-वीजा पर भी पाबंदी लगायी। वहीं दूसरी तरफ टैसलेट ने कुछ क्षेत्रों में बिना किसी पाबंदी के विदेशी मालिकाना हक, नीति के मोर्चे पर स्थिरता, भरोसा, समय पर विवाद समाधान, बौद्धिक संपदा का संरक्षण और ढांचागत क्षेत्र में लगातार निवेश की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने उम्मीद जतायी कि कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग ढांचागत क्षेत्र के निर्माण, द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के क्षेत्र में आगे भी जारी रहेगा। बयान में कहा गया है, ''सीईओ मंच के सदस्यों ने स्वास्थ्य और औषधि, एयरोस्पेस, रक्षा, ढांचागत क्षेत्र और विनिर्माण, उद्यमिता तथा छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने, ऊर्जा, पानी, पर्यावरण, वित्तीय सेवा, व्यापार तथा निवेश समेत अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के अवसर बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में सुधारों और नीतगत मोर्चे पर की गयी सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया।''दिसंबर 2014 में भारत और अमेरिका ने इस मंच का गठन किया। तब से यह यह पांचवां मौका है जब मंच की बैठक हुई है। यह एक महतवपूर्ण है मंच है जहां उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो कंपनियों को प्रभावित करती हैं। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय लाभ के लिये सहयोग को लेकर विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विलबर रोस ने की। बयान के अनुसार गोयल ने दोनों देशों में छोटी कंपनियों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने रोजगार बढ़ाने तथा क्षेत्र में कौशल विकास के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने मंच से आग्रह किया कि वह कोविड-19 के बाद की दुनिया के लिये आगे के रास्ते को लेकर योजना तैयार करने के मामले में अगुवा बने। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जेस्टर ने भारत-अमेरिका वाणिज्यक संबंधों में व्यापक संभावनाओं की ओर मंच का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मंच के प्रत्येक कार्यकारी समूह से वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिये नीति के स्तर पर सुझाव देने को कहा जिसे दोनों तरफ से क्रियान्वित किया जा सके। अमेरिका व्यापार के मामले में लगातार दूसरे वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष भागीदार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वित्त वर्ष में 88.75 अरब डॉलर रहा जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था।

RIL AGM: वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस देगा Jio

मुकेश अंबानी का ऐलान

भारत को बनाएंगे 2G मुक्त

पहली वर्चुअल ऑनलाइन AGM के जरिए पूरी दुनिया में फैले 26 लाख शेयरहोल्डर्स हुए शामिल

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस इंडस्ट्रीज के 43वें एजीएम में अंबानी ने 5G को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जियो भारत में 5 जी सर्विस शुरू करेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो आने वाले तीन सालों में आधा 50 करोड़ मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जियो ने संपूर्ण 5जी तकनीक विकसित कर ली है, जो भारत में वर्ल्ड क्लास 5उ सर्विस प्रदान करेगा। जैसे ही 5जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे, इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। फील्ड में इस्तेमाल के लिए अगले साल तक यह तकनीक तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास वर्तमान में 2जी फोन इस्तेमाल कर रहे 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है। उन्होंने बताया कि गूगल के साथ मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित 4G-5G स्मार्टफोन बनाएंगे। बता दें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वर्चुअल ऑनलाइन AGM के जरिए भारत समेत अमेरिका, यूके, कनाडा, जापान, हांगकांग समेत पूरी दुनिया में फैले 26 लाख शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया।

जियो प्लैटफॉर्म में गूगल 33,737 करोड़ रुपये का निवेश करेगा

आधुनिक मानव इतिहास में कोरोना संकट सबसे विघटनकारी घटना है। हालांकि, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और दुनिया तेजी से प्रगति करेंगे, अधिक समृद्धि और विकास की एक नई गुणवत्ता COVID संकट के बाद हासिल करेंगे।मुकेश अंबानी ने निवेशकों का स्वागत किया। मुकेश अंबानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रिलायंस अब सच्चे मायनों में कर्जमुक्त कंपनी बन गई है। इस लक्ष्य को मार्च 2021 की डेडलाइन से पहले ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट जियो, रिटेल और ओटूसी के लिए ग्रोथ प्लान में मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जियो प्लैटफॉर्म में गूगल 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि गूगल के निवेश के साथ ही जियो प्लैटफॉर्म्स के लिए पूंजी जुटाने का काम पूरा हो गया है।

जियो और गूगल मिलकर भारत को 2G-मुक्त बनाएंगे

मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो साथ मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, जो एंट्री लेवल के 4G/5G स्मार्टफोन के लिए होगा। जियो और गूगल मिलकर भारत को 2G-मुक्त बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5जी युग के दरवाजे पर खड़ा है। हमारा प्रयास वर्तमान में 2जी फोन इस्तेमाल कर रहे 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना होगा। वहीं एजीएम में फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के वीडियो संदेश भी चलाए गए

RIL सबसे ज्यादा जीएसटी और वैट देने वाली कंपनी

इससे पहले अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बताते हुए कहा कि आरआईएल देश की सबसे ज्यादा जीएसटी और वैट देने वाली कंपनी है। यह वैल्यू में करीब 69372 करोड़ रुपये है. वहीं आरआईएल ने पिछली बार 8 हजार करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स भरा। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।

ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने नए Jio TV+ की खूबियां बताई

मुकेश अंबानी के बाद ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने नए Jio TV+ की खूबियां बताई। इस नए Jio TV+ में नेटफ्लिक्स, अमेजन, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसे तमाम ओटीटी चैनल होंगे, जिनमें लॉगइन के लिए अलग-अलग आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो मार्ट को वॉट्सऐप की तकनीक के साथ पेश किया जाएगा। जियो मार्ट से किराना स्टोर्स को न केवल बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि कमाई भी बढ़ेगी।

JioMart पेश करते हुए ईशा अंबानी ने बताया कि इस तकनीक से वर्तमान किराना दुकानों को 48 घंटों के अंदर सेल्फ स्टोर में तब्दील हो जाएगा। इससे ग्राहकों का अनुभव भी पूरी तरह बदल जाएगा। जियो मीट के बारे में ईशा अंबानी ने बताया कि यह एक सस्ता और बेहद सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसके अलावा महज 75 ग्राम वजन वाले जियो ग्लास डिवाइस में मिक्स रियल्टी से जुड़ी सर्विसेज होंगी। यह सिंगल केबल से कनेक्ट होगा. इसमें 25 ऐप्स होंगे, जो एआर तकनीक वाली वीडियो मीटिंग में मदद करेगी।

आरआईएल के शेयर लुढ़के

एजीएम के दौरान रिलायंस के शेयर लुढ़कने लगे और 3.71% गिरकर 1845 रुपये पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं एजीएम के पहले कंपनी का शेयर ऐतहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका था। बुधवार के कारोबार में आरआईएल का शेयर करीब 2.12 फीसदी मजबूत होकर 1957 रुपये पर पहुंच गया। एजीएम के दौरान यह गिरकर 1910 रुपये पर आ गया। इससे पहले मंगलवार को शेयर 1917 रुपये पर बंद हुआ था। 23 मार्च को 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर 867 रुपये से शेयर में अबतक करीब 125 फीसदी की तेजी आ चुकी है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जुलाई महीने के लिए वित्त योजनाओं की घोषणा की

यारिस और ग्लांजा पर 55% आश्वस्त बायबैक की अनूठी पेशकश की शुरुआत

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए विशेष फाइनेंस स्कीम की घोषणा की। इसका मकसद खरीदने के निर्णय को आसान करना है। विशेष लाभ की विस्तृत श्रृंखला में अनूठी बायबैक पेशकश से लेकर कुछ सबसे निम्न ईएमआई शामिल हैं। ये पेशकशें हाल की ग्राहक केंद्रित पहल के क्रम में है जिसे कंपनी ने पेश किया था ताकि खरीद की प्रक्रिया और आसान, पहुंच में तथा सभी ग्राहकों के लिए तनाव मुक्त हो सके। नई डील्स में एक अनूठी आश्वस्त बायबैक पेशकश है जो यारिस और ग्लांजा पर 55ङ्क है। इसके अलावा, कंपनी ने कई अन्य उल्लेखनीय योजनाएं शुरू की हैं। इनमें इनोवा और क्रिस्टा के लिए 9999 रुपए की निम्न ईएमआई योजना शामिल है। इसके अलावा, देश में टोयोटा के सभी मॉडल पर तीन महीने की ईएमआई टालने की पेशकश है ताकि ग्राहकों की वित्तीय योजना को स्थिर रखा जा सके। पेशकशों के विशिष्ट और विशेष सेट पर टिप्पणी करते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड सर्विसेज श्री नवीन सोनी ने कहा, 'टोयोटा में हम 'ग्राहक सबसे पहले' के दर्शन पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप काम करना है और इसके लिए शीघ्र, किफायती, पारदर्शी और व्यैक्तिक सेवाएं मुहैया कराना है। अच्छी खबर यह है कि बाजार में हमें कुछ अच्छी गति देखने तो मिली हैं। इससे मई में जितनी बिक्री हुई थी उसके मुकाबले बिक्री में दूनी वृद्धि हुई है। ग्राहकों का भरोसा और ध्यान हासिल करने में हमें जिन अन्य घटकों से सहायता मिली है वे हैं नई और अभिनव वित्तीय योजनाएं जो हम अपने ग्राहकों को इस मुश्किल समय में आवाजाही की उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देते रहे हैं। हममें भरोसा करने के लिए हम अपने ग्राहकों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम ऐसी योजनाएं लाना जारी रखना चाहते हैं ताकि चुनने के लिए सबसे अनूठी पेशकशें की जाती रहें। सभी टोयोटा मॉडल के लिए ईएमआई योजनाएं और ग्लांजा तथा यारिस के लिए 55ङ्क आश्वस्त बायबैक पेशकश ग्राहकों को टोयोटा वाहन खरीदने के अपने सपने बगैर किसी देरी के पूर्ण करने में सहायता करेगी।'

जेब में आ जाएगा 'शाओमी का एयर पंप'

टायर में कहीं भी भरें हवा

नई दिल्ली। टेक कंपनी शाओमी केवल स्मार्टफोन्स तक ही सीमित नहीं है और ढेर सारे गैजेट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स का इकोसिस्टम तैयार कर रही है। भारत में कंपनी स्मार्टफोन्स के अलावा टीवी और होम अप्लायंसेज भी लेकर आई है। अब शाओमी ने Mi Portable Electric Air Compressor इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और इस एयर पंप की मदद से कहीं भी टायर में हवा भरी जा सकेगी। इसे चीन और यूके मार्केट में पहले ही उतारा जा चुका है।

शाओमी के इस एयर पंप की मदद से बाइक से लेकर कार तक के किसी भी टायर में हवा भरी जा सकती है और यह पंप बिल्ट-इन लिथियम बैटरी के साथ आता है। इसका मतलब है कि यूजर्स इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। हालांकि, भारत में यह स्पेशल क्राउडफंडिंग प्राइस पर खरीदा जा सकेगा। इस पोर्टेबल एयर कंप्रेशर में 'ऑटोफिल टू प्रीसेट एंड स्टॉप' जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इस एयर कंप्रेशर का लुक सिंपल और स्मूद है, साथ ही इसे पोर्टेबल फील के साथ डिजाइन किया गया है।

ऑटो-शटऑफ फीचर

शाओमी के नए एयर कंप्रेशर में 2000ङ्क की बिल्ट-इन बैटरी दी गई है, जो तीन घंटे तक का बैकअप दे सकती है। इसे माइक्रोयूएसबी पोर्ट की मदद से चार्ज किया जा सकता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल प्रेशर गॉज दिया गया है और ऑटो-शटऑफ कैपेबिलिटी भी दी गई है। इतने के बावजूद इसका डिजाइन इतना छोटा है कि यह आसानी से एक हथेली में समेटा जा सकता है। यूजर्स इसे अपनी कार या बैगपैक में रखकर सफर कर सकते हैं।

इतनी रखी गई कीमत

शाओमी के पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेशर को एक स्पेशल क्राउडफंडिंग प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस की कीमत 2,299 रुपये रखी गई है और इसका ओरिजनल प्राइस 3,499 रुपये रखा गया है। जो भी यूजर यह प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उन्हें शाओमी की ऑफिशल साइट पर जाकर इसे ऑर्डर करना होगा। हालांकि, इस डिवाइस की शिपिंग 10 अगस्त, 2020 से शुरू होगी। कंपनी ने अगले 10 दिन में इसके 4,000 यूनिट्स बेचने का टारगेट रखा है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।